'ज्ञान साझी विरासत है और इसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में छिपाकर नहीं रखा जाना चाहिए' — लोक सभा अध्यक्ष

जेनेवा, 24 अक्तूबर 2016 : लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज जेनेवा में ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में 'सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में ब्रिक्स संसदीय सहयोग' विषय पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि सतत विकास लक्ष्यों में सभी सरकारों के लिए कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं ताकि विश्व में रहन सहन की स्थितियां बेहतर हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान एक साझी विरासत है और इसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में छिपाकर नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए एक अनौपचारिक कार्य दल की स्थापना पर जोर दिया।

श्रीमती महाजन ने कहा कि भारत की संसद ने सभी लोगों के कल्याण के लिए बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जैसे अनेक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किए हैं और यही सतत विकास लक्ष्यों का भी उद्देश्य है। सतत विकास लक्ष्यों को स्वीकार करने से पहले भी भारत की बढ़ती आबादी की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ अनेक योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जिससे पता चलता है कि सतत विकास लक्ष्यों और भारत की विकास योजना में गहरा तालमेल है।

लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती वित्त व्यवस्था की है और दूसरी चुनौती प्रौद्योगिकी से जुड़ी है। वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का एक प्रभावी तरीका है इस कार्य में कॉर्पोरेट जगत को शामिल करना ताकि कॉर्पोरेट घराने अपनी

सामाजिक जिम्मेदारी के नाते विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास में शामिल हों। जहाँ तक प्रौद्योगिकी की बात है, उन्होंने विशेष रूप से विकासशील देशों को वैश्विक प्रौद्योगिकी अंतरित किए जाने के लिए विश्वसनीय तंत्र विकसित करने पर जोर दिया। इस बात का उल्लेख करते हुए कि हमारी अगली चुनौती समावेशी आर्थिक विकास को बढावा देना और लोक सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान करना है, उन्होंने खामियों को दूर करने और सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए हमारे मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर कर नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जहाँ तक अन्य चुनौतियों की बात है, उन्होंने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, साफ़-सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने पर जोर दिया।

श्रीमती महाजन ने कहा कि बाधाओं को दूर करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए संसदों और सांसदों को इन लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए। उन्होंने प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि लोक सभा की इस विषय पर नियमित रूप से विचार करने और प्रत्येक सत्र में एक दिन केवल सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा के लिए नियत करने की योजना है।

इस वर्ष अगस्त में जयपुर में हुई ब्रिक्स महिला सांसद मंच की बैठक के दौरान स्वीकार की गई जयपुर घोषणा का उल्लेख करते हुए श्रीमती महाजन ने कहा कि जयपुर घोषणा में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने के संकल्प की घोषणा की गई थी।